Carp and Common Carp are produced under this programme.

(e) Out of 28 commercial fish seed farms/hatcheries sanctioned so far, 20 fish seed farms/hatcheries have been completed and the remaining 8 fish seed farms/hatcheries are in various stages of construction.

लघु और कुटीर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापनार्थ प्रोत्साहन

*180. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अद्यतन तकनीकी जानकारी के आधार पर सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में लघु और कुटीर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापनार्थ जानकारी उपलब्ध कराने और प्रोत्साहन देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस संबंध में भविष्य में और क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) कुटीर और लघु उद्योग क्षेत्र में अनेक षि-आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। इन यूनिटों के विकास के लिए विभिन्न वित्तीय और अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इनमें निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की पहचान करने, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, किराया-खरीद आधार पर मशीनरी आदि की व्यवस्था करने में सहायता देना शामिल है। 19 खाद्य वस्तुओं को लघु क्षेत्र में ही उत्पादन करने के लिए आरक्षित किया गया है।

विविधीकृत समुद्री पदार्थों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पैकेजिंग करने में प्रौद्योगिकी का उच्चश्रेणीकरण करने तथा नयी प्रौद्योगिकी लागू करने हेतु विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है।

Complaint lodged by CITU to ILO

1153. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the Centre of Indian Trade Unions (CITU) had lodged a complaint to International Labour Office (Regd. as case No. 1479) in 1988;

(b) if so, what are the details of the complaint; and

(c) the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALVIYA): (a) Yes Sir, the Centre of Indian Trade Union (CITU) had lodged the complaint.

(b) Centre of Indian Trade Unions alleged that the Executive Committee of their affiliated Heavy Water Project Employees Union, which was the majority union, was wrongfully dislodged with the help of the agencies of the Government and a rival union was recognised by the management.

(c) According to the facts available the Heavy Water Project Employees Union got split-up in May 87 and the management extended provisional recognition to the new Executive Committee only after Labour Commissioner had verified that the new Executive was validly elected and also had the majority on its side. The Ministry of Law had endorsed this view.

Central assistance to Andhra Pradesh for Tribal Sub-Plan

1154. SHRI GOPALA RAO, RAO: Will the Minister of WELFARE be